उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को पेश किए गए बजट में प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। औद्योगिक विस्तार, अवस्थापना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक पर्यटन पर विशेष फोकस करते हुए सरकार ने 27,103 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले बजट से 13 प्रतिशत अधिक है। मेरठ और पश्चिमी यूपी को रिंग रोड, फ्लाईओवर, सोलर सिटी जैसी सौगातें मिली हैं।

एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर

बढ़ावा

प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यस्था बनाने का लक्ष्य जल्द हासिल करने के लिए सरकार अवस्थापना व औद्योगिक विकास को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसके लिए बजट में 27,103 करोड़ रुपये का प्रबंध किया है। यह राशि पिछले बजट की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण तथा नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के तहत पांच हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए भी पिटारा खोला है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कारीडोर परियोजना को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तक 200 रक्षा उद्योगों की स्थापना के लिए 35,280 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। सरकार ने बजट में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण को जारी रखने के लिए 2,374 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है। फारेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट (एफडीआई) व फार्च्यून-500 कंपनियों के निवेशकों के लिए प्रोत्साहन नीति-2023 के लिए 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गई है।

एक्सप्रेस-वे की कनेक्टिविटी बढ़ाएगी सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि अवस्थापना व औद्योगिक विकास के लिए भी बजट में खास व्यवस्था की गई है। आगरा-लखनऊ से हरदोई-फर्रुखाबाद गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से प्रयागराज, मीरजापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र तक यानी शक्तिनगर तक इसका विस्तार होगा। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ-हरिद्वार तक ले जाने के लिए भी बजट में घोषणा की गई है।

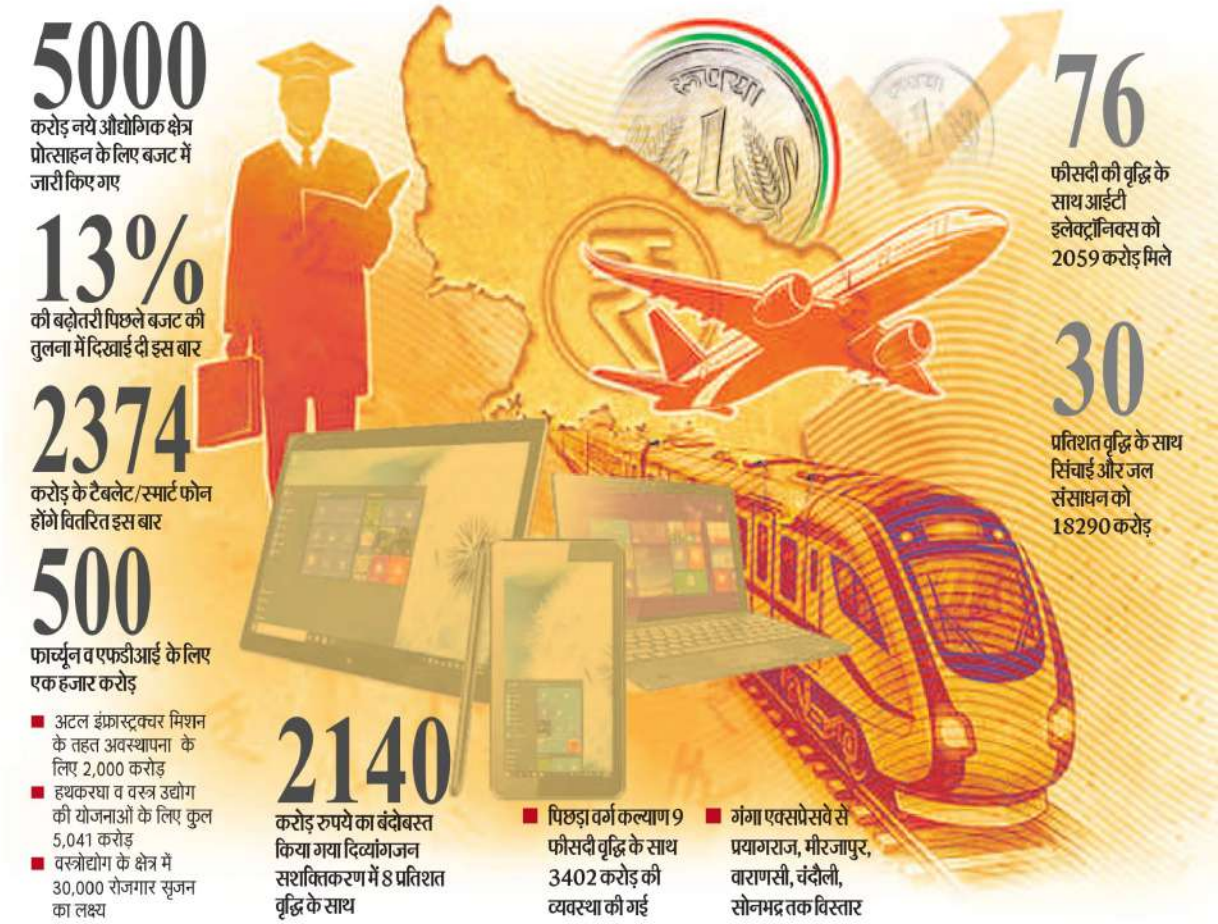

5000 करोड़ नये औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन के लिए बजट में जारी किए गए

13% की बढ़ोतरी पिछले बजट की तुलना में दिखाई दी इस बार

2374 करोड़ के टैबलेट/स्मार्ट फोन होंगे वितरित इस बार

500 फार्च्यून व एफडीआई के लिए एक हजार करोड़

- अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत अवस्थापना के लिए 2,000 करोड़
- हथकरघा व वस्त्र उद्योग की योजनाओं के लिए कुल 5,041 करोड़
- वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य

2140 करोड़ रुपये का बंदोबस्त किया गया दिव्यांगजन सशक्तिकरण में 8 प्रतिशत वृद्धि के साथ

- पिछड़ा वर्ग कल्याण 9 फीसदी वृद्धि के साथ 3402 करोड़ की व्यवस्था की गई
- गंगा एक्सप्रेसवे से प्रयागराज, मीरजापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र तक विस्तार

76 फीसदी की वृद्धि के साथ आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स को 2059 करोड़ मिले

30 प्रतिशत वृद्धि के साथ सिंचाई और जल संसाधन को 18290 करोड़

आयुष सेवाओं के लिए 2,867 करोड़ की व्यवस्था

लखनऊ, विशेष संवाददाता। आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के राज्यमंत्री डा. दयाशंकर मिश्र दयालु ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट जनता के विकास की जरूरतों और सुशासन की प्रतिबद्धता की संकल्पना को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह बजट एक निर्णायक पहल है। आयुष मंत्री ने कहा कि प्रदेश में आयुष विभाग निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आयुष सेवाओं के लिये बजट में लगभग 2,867 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

बुलंदशहर को मिली पहली औद्योगिक योजना

मेरठ, मुख्य संवाददाता। प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को पेश किए गए बजट में मेरठ समेत पूरे वेस्ट यूपी के लिए विकास की कुछ बड़ी सौगातें दी गई हैं। इस बजट में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे क्षेत्र की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। बुलंदशहर को पहली औद्योगिक योजना दिये जाने की घोषणा हुई है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से पेश बजट में मेरठ में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 250 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, शहर में जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने हेतु रिंग रोड और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है। मेरठ, सहारनपुर सहित प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों को 'सोलर सिटी' के रूप में विकसित किया जाएगा, जो ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

बुलंदशहर के लिए यह बजट ऐतिहासिक रहा है, जहां पहली बार किसी बड़ी औद्योगिक योजना की शुरुआत की जा रही है। साथ ही, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के लिए प्रदेश स्तर पर 5041 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसका सीधा लाभ मेरठ समेत वेस्ट यूपी के बुनकरों को मिलेगा। सभी जिला अस्पताल में अत्याधुनिक इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर की स्थापना होगी।